श्री विमल किशोर शाह और अन्य

बनाम

श्री जयेश दिनेश शाह और अन्य

(सिविल अपील संख्या 8164/2016)

17 अगस्त, 2016

[जे. चेलमेश्वर और अभय मनोहर सेपरे, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-धारा 2 (बी), 2 (एच), 7 और 11-आवेदन धारा 11 मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए-न्यास विलेख में मध्यस्थता खंड को ध्यान में रखते हुए-लाभार्थियों के बीच विवाद को हल करने के लिए-आवेदन की उपलब्धता-आयोजितः आवेदन धारा 11 केवल तभी बनाए रखा जा सकता है जब अधिनियम की धारा 7 के अर्थ के भीतर वैध, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय 'मध्यस्थता समझौता' हो-मध्यस्थता खंड सहित न्यास विलेख की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। 2 (बी), 2 (एच) आर/डब्ल्यू. धारा 7 और इसलिए धारा 7 के अर्थ के भीतर लाभार्थियों के बीच एक 'मध्यस्थता समझौते' के रूप में नहीं माना जा सकता है-ट्रस्ट अधिनियम विशेष रूप से ट्रस्ट के संबंध में विवादों के संबंध में दीवानी अदालत की अधिकारिता प्रदान करता है, इस प्रकार निहित रूप से मध्यस्थता अधिनियम की प्रयोज्यता को बाहर करता है-इसलिए, आवेदन

धारा 11 रखरखाव योग्य नहीं है-न्यास अधिनियम, 1882। क़ानूनों की व्याख्याः जो कानून अदालतों के अधिकार क्षेत्र को हटा देता है, उसका आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है-इसके लिए व्याख्या के सख्त नियम की आवश्यकता होती है. यदि कोई क़ानून किसी विशिष्ट उपचार का प्रावधान करता है, तो यह क़ानून में दिए गए उपचार के अलावा किसी अन्य रूप के उपचार को मना करता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहाः

1. एक वैध, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय मध्यस्थता समझौते का गठन करने के लिए, धारा 7 में निहित आवश्यकताओं को सख्ती से पूरा करना होगा। ये आवश्यकताएँ, अन्य के अलावा, ये हैं (1) एक समझौता होना चाहिए (2) इसे लिखित रूप में होना चाहिए (3) पक्षों को ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए या दूसरे शब्दों में, समझौते पर संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर होने चाहिए और (4) ऐसे समझौते में एक मध्यस्थता खंड होना चाहिए। चार शर्तों में से किसी को भी पूरा करने में विफलता मध्यस्थता समझौते को अमान्य और अप्रवर्तनीय बना देगी और इसके परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर आवेदन को उसकी सीमा पर खारिज कर दिया जाएगा। मध्यस्थता खंड सहित न्यास विलेख अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (बी) और 2 (एच) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और इसलिए न्यास विलेख को

अधिनियम की धारा 7 के अर्थ के भीतर "मध्यस्थता समझौते" के रूप में नहीं माना जा सकता है। [111-जी-एच; 112-ए-बी; 116-सी-डी]

विजय कुमार शर्मा उर्फ मंजू बनाम रघुनाथन शर्मा उर्फ बाबूराम और अन्य 2010 (1) एस. सी. आर. 582:2010 (2) एस सी सी 486-पर भरोसा किया।

बिजॉय बल्लव कुंडू और एक अन्य बनाम तपेली रंजन कुंडू, ए. आई. आर. 1965 कलकत्ता 628-अनुमोदित।

1.2 प्रत्येक समझौते के मामले में हमेशा एक प्रस्ताव होता है और फिर उसकी स्वीकृति होती है, जो न्यास के निर्माण के मामले में आवश्यक नहीं है क्योंकि न्यास के मामले में न्यासी और लाभार्थी यद्यपि इसके निर्माण को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस तरह की स्वीकृति से वे केवल न्यास विलेख की शर्तों को पूरा करने का वचन देते हैं, जहां तक वह कानून के अनुसार हो। न्यास विलेख में मध्यस्थता से संबंधित खंड कई खंडों में से एक है। अन्य खंड जो न्यासियों और लाभार्थियों को कई प्रकार के निर्देशों से संबंधित हैं जैसे कि न्यास का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, न्यास की राशि कैसे खर्च की जानी चाहिए आदि न्यासियों या/और लाभार्थियों के बीच समझौते की प्रकृति में नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, न्यास विलेख को स्वीकार करके, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यासी या लाभार्थी आपस में इस बात पर सहमत हुए हैं कि उन्हें धन कैसे खर्च

करना चाहिए या उन्हें न्यास के मामलों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए या कोई लाभ कैसे प्राप्त करना चाहिए। इसलिए, इस तरह की किसी भी गतिविधि को करने के लिए न्यासियों या लाभार्थियों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होना है तो न्यासियों/लाभार्थियों को न्यास विलेख के प्रत्येक खंड के संबंध में प्रस्ताव और स्वीकृति देनी होगी। तब यह सरासर बेतुकी बात होगी और इसलिए ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पेरा 41 और 42] [119-डी-जी]

1.3 किसी समझौते का खंड, जो निजी मध्यस्थता के माध्यम से ऐसे समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने का प्रावधान करता है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करता है और न्यायालयों की अधिकारिता को हटाने का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मध्यस्थता अधिनियम एक ऐसा कानून है, जो सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हटाने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, मध्यस्थता के माध्यम से किसी समझौते के पक्षों के बीच विवादों को तय करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस तरह के खंड के लिए यह पता लगाने के लिए व्याख्या के सख्त नियम की आवश्यकता होती है कि क्या यह अधिकारिता को हटाने का प्रावधान करता है और, यदि ऐसा है, तो किस न्यायालय न्यायाधिकरण/प्राधिकरण के लिए, जैसा भी मामला हो। वर्तमान मामले में,

जब व्याख्या का यह सिद्धांत लागू किया जाता है, तो यह पाया जाता है कि खंड 20 मध्यस्थ को लाभार्थियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार, खंड 20 अधिनियम की धारा 2 (बी), 2 (एच) और 7 की कठोरता को संतुष्ट नहीं करता है। [पैरा 43] [119-एच; 120-ए-सी]

1.4 ट्रस्ट डीड में खंड 20, जो ट्रस्ट के लाभार्थियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों/मतभेदों के निपटारे का प्रावधान करता है, अधिनियम की धारा 7 के अर्थ के भीतर लाभार्थियों के बीच एक मध्यस्थता समझौते का गठन नहीं करता है। ट्रस्ट अधिनियम की धारा 7, 11, 34, 36, 41, 45, 46, 49, 53, 71, 72, 73 और 74 में विशेष रूप से न्यास के लेखक, न्यासी और लाभार्थियों को न्यास विलेख और न्यास अधिनियम के तहत अपने अधिकार कर्तव्यों, हटाने और दायित्वों के संबंध में अपनी कई शिकायतों को उजागर करने के लिए उपलब्ध कानूनी उपचार प्रदान किए गए हैं। ये धाराएँ, विशिष्ट शब्दों में, सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करती हैं और यह प्रावधान करती हैं कि एक पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों के न्यायनिर्णयन के लिए मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख सिविल न्यायालय से संपर्क कर सकता है। यह स्पष्ट रूप से विधायिका के इरादे को दर्शाता है कि विधायिका ट्रस्ट अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने के लिए केवल दीवानी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र

प्रदान करने का इरादा रखती है। [पैरा 54) [123-डी-ई] बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक बनाम एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य। 2011 (7) एस. सी. आर. 310: (2011) 5 एस. सी. सी. 532-पर निर्भर था। धुलाभाई आदि। बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.: ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 78:1968 एस. सी. आर. 662-इसके बाद।

1.4 न्यास विलेख में खंड 20, जो न्यास के लाभार्थियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों/मतभेदों के निपटारे का प्रावधान करता है, अधिनियम की धारा 7 के अर्थ के भीतर लाभार्थियों के बीच एक मध्यस्थता समझौते का गठन नहीं करता है। [पैरा 44] [120-डी]

2.1 न्यास अधिनियम की धारा 7, 11, 34, 36, 41, 45, 46, 49, 53, 71, 72, 73 और 74 में न्यास के लेखक, न्यासी और लाभार्थियों को न्यास विलेख और न्यास अधिनियम के तहत अपने अधिकार कर्तव्यों, हटाने और दायित्वों के संबंध में अपनी कई शिकायतों को उजागर करने के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कानूनी उपाय प्रदान किए गए हैं। ये धाराएँ, विशिष्ट शब्दों में, सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करती हैं और यह प्रावधान करती हैं कि एक पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों के न्यायनिर्णयन के लिए मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख सिविल न्यायालय से संपर्क कर सकता है। यह स्पष्ट रूप से विधायिका के इरादे को दर्शाता है कि विधायिका ट्रस्ट अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों को तय

करने के लिए केवल दीवानी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का इरादा रखती है। [पैरा 54) [123-डी-ई]

बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक बनाम एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य 2011 (7) एस. सी. आर. 310: (2011) 5 एस. सी. सी. 532-पर निर्भर था।

धुलाभाई आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 78:1968 एस. सी. आर. 662-इसके बाद।

2.2 यद्यपि न्यास अधिनियम दस्तावेज न्यास अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने के लिए अन्य अधिनियमों की प्रयोज्यता के संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिबंध प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन न्यास, न्यासियों और लाभार्थियों से संबंधित विवादों को निजी मध्यस्थता के माध्यम से तय करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की प्रयोज्यता के बहिष्करण का एक निहित प्रतिबंध मौजूद है। दूसरे शब्दों में, जब न्यास अधिनियम न्यास, न्यासियों और लाभार्थियों के साथ व्यापक रूप से व्यवहार करता है और सभी पीड़ित व्यक्तियों को न्यास विलेख और न्यास अधिनियम से उत्पन्न होने वाले अपने विवादों के निवारण के लिए मूल मूल अधिकार क्षेत्र के सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देकर पर्याप्त और पर्याप्त उपचार प्रदान करता है, तो न्यास के मामलों से संबंधित किसी भी विवाद, जिसमें न्यासी और लाभार्थी के बीच

उनके अधिकार, कर्तव्यों, दायित्वों, हटाने आदि के संबंध में विवाद शामिल है, का निर्णय मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेकर नहीं किया जा सकता है। इस तरह के विवादों का निर्णय न्यास अधिनियम के तहत निर्दिष्ट दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाना है। [पैरा 58) (124-एफ-एच]

2.3 यह व्याख्या का सिद्धांत है कि जहां एक विशिष्ट उपचार दिया जाता है, यह उस व्यक्ति को वंचित कर देता है जो क़ानून द्वारा दिए गए उपचार के अलावा किसी अन्य प्रकार के उपचार पर जोर देता है। यह सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू होता है, क्योंकि न्यास अधिनियम एक दायित्व पैदा करता है और न्यास विलेख में निर्दिष्ट कई शर्तों के अलावा बसने वाले, न्यासी और लाभार्थियों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है और सिविल न्यायालय में आवेदन दायर करके इसके प्रवर्तन के लिए एक विशिष्ट उपाय प्रदान करता है। इसलिए, चूंकि न्यास विलेख, न्यासियों और लाभार्थियों के संबंध में विवादों को तय करने के लिए न्यास अधिनियम के तहत पर्याप्त और पर्याप्त उपाय प्रदान किया गया है, इसलिए ऐसे विवादों को तय करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम के तहत प्रदान किया गया उपाय निहितार्थ से वर्जित है। [पैरा 59] [125-ए, बी-डी]

प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटड बनाम कमलाकर शांताराम वाडके और अन्य ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 2238: 1976 (1) एस. सी. आर. 427-पर निर्भर था।

जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 12 संस्करण, पृष्ठ 763-764-संदर्भित।

3. न्यास विलेख और न्यास अधिनियम से उत्पन्न न्यास, न्यासियों और लाभार्थियों से संबंधित विवाद पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बावजूद मध्यस्थ द्वारा तय किए जाने में सक्षम नहीं हैं। ए फोर्टियोरी-यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा दायर आवेदन इस आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं है कि पहला, यह अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (बी) और 2 (एच) के अर्थ के भीतर एक "मध्यस्थता समझौते" पर आधारित नहीं है और दूसरा, यह मानते हुए कि एक मध्यस्थता समझौता (न्यास विलेख का खंड 20) मौजूद है, फिर भी उसमें निर्दिष्ट विवाद गुण-दोष के आधार पर अपने निर्णय के लिए निजी मध्यस्थता को भेजे जाने में सक्षम नहीं हैं। अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन को खारिज किया जा सकता है क्योंकि यह बनाए रखने योग्य नहीं है। [पैरा 61 और 65) [125-एफ-जी; 126-सी-डी]

एम.सी. चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर त्रिवेंद्रम 1969 (2) एस. सी. आर. 953: (1970) 1 एस. सी. सी 658-प्रतिष्ठित।

मामला कानून संदर्भ

2010 (1) एस. सी. आर. 582 भरोसा किया पैरा 25

ए. आई. आर. 1965 कलकत्ता 628 अनुमोदित पैरा 36

2011 (7) एस. सी. आर. 310 भरोसा किया पैरा 48

1968 एस. सी. आर. 662 के अनुसरण किया पैरा 55

1976 (1) एस. सी. आर. 427 भरोसा किया पैरा 59

1969 (2) एस. सी. आर. 953 विशिष्ट पैरा 60

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 8164/2016

2012 के मध्यस्थता आवेदन संख्या 278 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 06.03.2013 से।

शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, जय सावला, तुषार गोराडिया, सुश्री शिलपी चौधरी, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।

गौरव अग्रवाल, सुश्री यास्मीन ई. तोवासिया, अभिकल्प प्रताप सिंह, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय अभय मनोहर सप्रे, जे. 1 द्वारा दिया गया था। अनुमति दे दी गई।

2. यह अपील 2012 के मध्यस्थता आवेदन संख्या 278 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत मध्यस्थता आवेदन की अनुमति दी है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दायर किया गया है और बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री एस. आर. शाह को पक्षों के बीच विवादों को मध्यस्थता करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है।

3. इस अपील में शामिल मुद्दे की सराहना करने के लिए, जो एक संकीर्ण दिशा में स्थित है, प्रासंगिक तथ्यों को संक्षिप्त रूप से निर्धारित करना आवश्यक है।

4. श्री द्वारकादास लक्ष्मीचंद मोदी नामक व्यक्ति ने अपनी संपत्तियों के संबंध में ट्रस्ट के लेखक के रूप में "डीड ऑफ कायडी फैमिली ट्रस्ट" नामक एक पारिवारिक ट्रस्ट विलेख को निष्पादित किया, जिसे इसके बाद "सेटलर" कहा जाता है। बसने वाले ने ट्रस्ट डीड में छह नाबालिगों (अब बड़े) के पक्ष में प्यार और स्नेह से इस ट्रस्ट का गठन किया, अर्थात्, 1)

मास्टर विमल किशोर शाह, 2) मास्टर नैनेश किशोर शाह, 3) कुमार ग्रिश्मा किशोर शाह, 4) मास्टर जायेश दिनेश शाह, 5) मास्टर उत्पल दिनेश शाह और 6) मास्टर मोनी दिनेश शाह, (इसके बाद "लाभार्थी" के रूप में संदर्भित)। न्यास और उसकी संपत्तियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए, उपनिवेशवादी ने दो व्यक्तियों-श्री दिनेश नंदलाल शाह और श्रीमती सरयू किशोर शाह को प्रबंध न्यासी के रूप में नियुक्त किया।

5. न्यास विलेख का खंड 20, जो इस मामले के निपटारे के लिए प्रासंगिक है, यह प्रावधान करता है कि न्यास विलेख के किसी भी खंड या प्रावधान या विषय-वस्तु की व्याख्या के संबंध में प्रत्येक विवाद या मतभेद या न्यासियों के बीच कोई विवाद या न्यासियों और लाभार्थियों के बीच विवाद या लाभार्थियों के बीच विवाद जब भी और जब भी उत्पन्न होंगे, उन्हें भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अनुसरण में हल किया जाएगा और मध्यस्थताओ का निर्णय अंतिम और मध्यस्थता के पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

6. दुर्भाग्य से, जैसा कि मामले के रिकॉर्ड और पक्षों के आचरण से प्रतीत होता है, बसने वाले की इच्छा और भावना पूरी नहीं हो सकी जिसके लिए उसने ट्रस्ट का गठन किया था और इसके गठन के तुरंत बाद वार्डों पर कहीं न कहीं से, ट्रस्ट के मामलों और व्यवसाय को चलाने के तरीके के संबंध में अंतर लाभार्थियों के बीच मतभेद पैदा हो गए। इसके कारण

ट्रस्टीशिप के एक ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ट्रस्ट के कामकाज के तरीके, इसके मामलों और ट्रस्ट के खातों की मांग आदि के बारे में एक-दूसरे के खिलाफ आरोप और जवाबी आरोप लगाते हुए अपने वकीलों के माध्यम से लाभार्थियों के बीच कानूनी नोटिसों का आदान-प्रदान किया गया। नोटिस में यह भी मांग की गई थी कि चूंकि पक्ष अपने विवादों/मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए ऐसे सभी विवादों/मतभेदों को न्यास विलेख के खंड 20 के अनुसार मध्यस्थ के निर्णय के लिए भेजा जाना चाहिए।

7. चूंकि पक्षकार विवादों/मतभेदों का निपटारा नहीं कर सकते थे और न ही वे सौहार्दपूर्ण ढंग से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमत हो सकते थे, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 (लाभार्थियों का एक समूह) ने अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थता आवेदन संख्या 278/2012 होने के कारण बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपीलकर्ताओं (लाभार्थियों के अन्य समूह) के खिलाफ एक आवेदन दायर किया, जिसमें अनुरोध किया गया था कि सभी विवादों/मतभेदों को, जो पक्षकारों के बीच उत्पन्न हुए थे, न्यास विलेख के खंड 20 के संदर्भ में मध्यस्थ को भेजा जाए। आवेदन राहत का दावा करने के लिए उपरोक्त तथ्यों पर आधारित था।

8. इसमें अपीलकर्ताओं (उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं) ने आवेदन का विरोध किया। अन्य आधारों के अलावा, प्रतिस्पर्धा का मुख्य

कानूनी आधार यह था कि अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है। यह तर्क दिया गया कि जब अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी न तो न्यास विलेख के पक्षकार हैं और न ही न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने वाले इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं, तो उन्हें ऐसे न्यास विलेख का "पक्षकार" नहीं कहा जा सकता है और न ही ऐसे न्यास विलेख को अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (बी) और 2 (एच) के अर्थ के भीतर "मध्यस्थता समझौते" से बहुत कम "समझौता" कहा जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए अनिवार्य रूप से एक वैध और लागू करने योग्य मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व है, जिसका इस मामले में अभाव है, और इसलिए अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है और अकेले इसी आधार पर खारिज किया जा सकता है।

9. विद्वत नामित न्यायाधीश ने विवादित निर्णय द्वारा आवेदन को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि चूंकि आवेदन के पक्षकार न्यास विलेख के निष्पादन के समय नाबालिग थे, इसलिए वे न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ थे। उन्होंने आगे कहा कि अब सभी पक्ष बड़े हो गए हैं और उन्होंने अपने अल्पमत में लाभार्थियों के रूप में न्यास विलेख का लाभ उठाया है और फिर बहुमत प्राप्त करने पर, उन्हें अधिनियम की धारा 2 (एच) के अर्थ के भीतर न्यास विलेख में "पक्षकार" के रूप में रखा जाना

चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार जब लाभार्थियों को न्यास विलेख में पक्षकार बनाया जाता है, तो उन्हें न्यास विलेख के खंड 20 को लागू करके न्यास विलेख के मामलों से संबंधित उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही का सहारा लेने का अधिकार है।

10. इन निष्कर्षों के साथ, विद्वान न्यायाधीश ने न्यास विलेख के खंड 20 को लागू करने के लिए आगे बढ़े और श्री एस आर शाह-मुंबई शहर के पूर्व सिविल न्यायाधीश को आवेदन के पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों/मतभेदों को तय करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। यह इस आदेश के खिलाफ है, उत्तरदाताओं, जो ऊपर बताए गए लाभार्थियों के अन्य समूह हैं, ने व्यथित महसूस किया है और इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

11. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर नाफडे और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल को सुना।

12. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री शेखर नाफडे ने विवादित आदेश की वैधता और शुद्धता पर जोर देते हुए तीन बार दलीलें दी हैं।

13. सबसे पहले, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान नामित न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर आवेदन को अनुमति देने में गलती की। उनके प्रस्तुतिकरण में, आवेदन को विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जा सकता था।

14. दूसरे स्थान पर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि जब आवेदन के स्वीकृत पक्षकार, जो न्यास के लाभार्थी हैं, ने न्यास विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो उन्हें ऐसे न्यास विलेख में पक्षकार नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन दायर करने के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि एक वैध और लागू करने योग्य मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में होना चाहिए और उनके अनुसार, इस तरह के समझौते को लिखित रूप में कम किया जाना चाहिए और अंत में, अधिनियम की धारा 7 (4) के साथ पठित धारा 2 (एच) के तहत प्रदान किए गए आवेदन के पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यह आग्रह किया गया कि चूंकि उत्तरदाता कानून की इस बुनियादी आवश्यकता को साबित करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 11 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा दायर आवेदन अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (बी) और 2 (एच) की आवश्यकता का पालन न करने के कारण खारिज किया जा सकता है।

15. तीसरे स्थान पर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि ऊपर जो आग्रह किया गया है, उसके अलावा, ट्रस्ट के कार्य, बसने वालों द्वारा शिकायतों का निवारण करने के लिए अधिकार, दायित्व, निष्कासन, कर्तव्य और कानूनी उपाय, न्यासी और लाभार्थी भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (जिसे इसके बाद "ट्रस्ट अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा शासित हैं, जो उपरोक्त मामलों से निपटने के लिए अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, ऊपर उल्लिखित हितधारकों के बीच विवाद सहित ट्रस्ट के मामलों से संबंधित किसी भी विवाद को तय करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं हैं और हितधारकों का उपाय ट्रस्ट अधिनियम में निर्दिष्ट एक उपयुक्त मंच में अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेना होगा।

16. ये प्रस्तुतियाँ हैं, जिन्हें विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने तर्क में ट्रस्ट अधिनियम की योजना और इसके विभिन्न प्रावधानों और निर्णयों के संदर्भ में विस्तार से बताया था, जो इन मुद्दों से निपटते थे।

17. जवाब में, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील, श्री गौरव अग्रवाल ने नामित न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष का समर्थन किया और इस अपील में कोई हस्तक्षेप नहीं करने के लिए इसके समर्थन के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अधिनियम और मामले के कानून के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपनी दलीलों को भी विस्तार से बताया।

18. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर नाफडे की दलीलों में बल पाते हैं।

19. इस अपील में विचार के लिए मूल प्रश्न यह है कि क्या न्यास विलेख में एक खंड, जो न्यास के लाभार्थियों के बीच मध्यस्थता के माध्यम से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का प्रावधान करता है, अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (बी) और 2 (एच) के अर्थ के भीतर एक "मध्यस्थता समझौते" का गठन कर सकता है और क्या अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा दायर आवेदन को बनाए रखने योग्य माना जा सकता है?

20. अधिनियम की धारा 2 (बी) और 2 (एच) और धारा 7 मामले में शामिल प्रश्न की जांच करने के लिए प्रासंगिक हैं। ये खंड निम्नानुसार हैं:

2. परिभाषा ..(1)

(a)---

(b)---(h)पक्षकार" से मध्यस्थता समझौते का पक्षकार अभिप्रेत है।

7 मध्यस्थता समझौता-(1) इस भाग में, "मध्यस्थता समझौता" का अर्थ पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता को उन सभी या कुछ विवादों को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता है जो उत्पन्न हुए हैं या जो एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं।

(2) एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है।

(3) मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा।

(4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में है यदि यह

(ए) पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ में निहित है;

(बी) पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करता है; या

(सी) दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।

(5) मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है

और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए।

21. धारा 2 (बी) "मध्यस्थता समझौते" को परिभाषित करती है और यह निर्धारित करती है कि मध्यस्थता समझौते का अर्थ धारा 7 में संदर्भित मध्यस्थता समझौता है जबकि धारा 2 (एच) "पक्ष" शब्द को मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष के रूप में परिभाषित करती है।

22. धारा 7 "मध्यस्थता समझौते" को परिभाषित करती है। इसके पाँच उपखंड हैं। उप-धारा (l) में यह प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थता समझौते का अर्थ पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता को उन सभी या कुछ विवादों को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता है जो एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं। उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि मध्यस्थता समझौता किसी अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में हो सकता है या यह एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। उप-धारा (3) में कहा गया है कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा। उप-धारा (4), जिसमें तीन खंड (ए), (बी) और (सी) हैं, कहती है कि एक दस्तावेज जिसमें मध्यस्थता समझौता होता है, उस पर पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। खंड (बी) पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों के आदान-प्रदान द्वारा एक

मध्यस्थता समझौते को मान्यता देता है जो ऐसे समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करता है और खंड (सी) दावे और बचाव के बयानों के आदान-प्रदान द्वारा एक मध्यस्थता समझौते को भी मान्यता देता है जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।

23. उपरोक्त धाराओं को एक साथ पढ़ने से पता चलता है कि एक वैध, बाध्यकारी और लागू करने योग्य मध्यस्थता समझौते का गठन करने के लिए, धारा 7 में निहित आवश्यकताओं को सख्ती से पूरा करना होगा। ये आवश्यकताएँ, अन्य के अलावा, ये हैं (1) एक समझौता होना चाहिए (2) इसे लिखित रूप में होना चाहिए (3) पक्षों को ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए या दूसरे शब्दों में, समझौते पर संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर होने चाहिए और (4) ऐसे समझौते में एक मध्यस्थता खंड होना चाहिए।

24. दूसरे शब्दों में, एक वैध और लागू करने योग्य मध्यस्थता समझौते के गठन के लिए उपरोक्त चार शर्तें अनिवार्य हैं। चार शर्तों में से किसी को भी पूरा करने में विफलता मध्यस्थता समझौते को अमान्य और अप्रवर्तनीय बना देगी और इसके परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर आवेदन को उसकी सीमा पर खारिज कर दिया जाएगा।

25. यह सवाल कि एक वैध और प्रवर्तनीय मध्यस्थता समझौते के गठन के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, विजय कुमार शर्मा उर्फ मंजू बनाम रघुनाथन शर्मा उर्फ बाबूराम और अन्य 2010 (2) एससीसी 486 में इस अदालत के समक्ष विचार के लिए सामने आई। इस मामले में, इस संदर्भ में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या वसीयत में एक खंड, जिसमें यह प्रावधान है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत की गई संपत्तियों के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा नामित मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा, क्या ऐसा खंड या/और वसीयत को अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (बी) के अर्थ के भीतर एक मध्यस्थता समझौते के रूप में माना जा सकता है, जिसका उद्देश्य विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता को लागू करना है। यह प्रश्न निम्नलिखित तथ्यों पर उठा।

26. पिता ने अपने एक बेटे के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की जिसके तहत उन्होंने उसे अपना एक घर विरासत में दिया। उनका एक और बेटा था जिसे उन्होंने उक्त घर में कोई हिस्सा नहीं दिया था। वसीयत में, पिता ने दो निष्पादक नियुक्त किए और व्यक्त किया कि यदि वसीयत की गई संपत्ति के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो एक नामित मध्यस्थ इस तरह के विवाद का फैसला करेगा। पिता की मृत्यु पर, एक बेटे ने वसीयत की गई संपत्ति में अपने एक तिहाई हिस्से की घोषणा के

लिए मुकदमा दायर किया और विभाजन की भी मांग की, जबकि दूसरे बेटे ने वसीयत के बल पर मुकदमा दायर किया और अपने सभी भाइयों और बहनों को छोड़कर अपने अनन्य स्वामित्व का दावा किया। मुकदमों को मुकदमे के लिए जोड़ा गया था।

27. दोनों निष्पादक, जिन्हें मुकदमों में पक्षकार भी बनाया गया था, ने अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें तर्क दिया गया था कि वसीयतकर्ता ने वसीयत में और एक अलग घोषणा में भी घोषणा की थी कि वसीयत किए गए घर के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, उसे अपने निर्णय के लिए एक नामित मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि इसके आलोक में, पक्षों द्वारा दायर दो दीवानी मुकदमे खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि पक्षकारों को नामित मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में खुद को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि मध्यस्थ वसीयत/घोषणा में निहित मध्यस्थता खंड के अनुसार विवादों का फैसला करने में सक्षम हो सके।

28. ट्रायल कोर्ट ने अधिनियम की धारा 8 के तहत निष्पादकों द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और इसके परिणामस्वरूप, पक्षकारों को नामित मध्यस्थ से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ मुकदमों को खारिज कर दिया। तदनुसार, एक पक्ष ने नामित मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र

में खुद को प्रस्तुत किया और अपना दावा दायर किया, जबकि दूसरे पक्ष ने मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पक्षों के बीच न तो कोई मध्यस्थता समझौता था और न ही उन्होंने कभी अपने दिवंगत पिता द्वारा वसीयत या किसी घोषणा पर हस्ताक्षर किए और न ही किसी नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपनी सहमति दी। इसलिए, उन्होंने मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत को क्षेत्राधिकार के बिना होने के रूप में चुनौती दी।

29. इसके कारण नामित मध्यस्थ ने मध्यस्थता कार्यवाही से नाम वापस ले लिया, जिसने बदले में, राजस्थान के उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 11 के तहत एक बेटे द्वारा आवेदन दायर करने को जन्म दिया। उन्होंने उसमें पहले नामित मध्यस्थ के स्थान पर नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की। आवेदन को दूसरे बेटे द्वारा उसी आपत्ति को दोहराते हुए चुनौती दी गई थी, जिसे उन्होंने पहले उठाया था, अर्थात्, पक्षों के बीच कोई वैध और प्रवर्तनीय मध्यस्थता समझौता नहीं है और न तो वसीयत और न ही घोषणा उनके बीच किसी भी विवाद को तय करने के लिए कोई मध्यस्थता समझौते का गठन करती है।

30. मुख्य न्यायाधीश के विद्वत नामित ने आपत्ति को खारिज कर दिया और आवेदन को अनुमति दी और सदन के संबंध में आवेदन के पक्षों

के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने के लिए नए मध्यस्थ को नियुक्त किया। यह वह आदेश है, जिसे इस न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए विशेष अनुमति में आक्षेपित किया गया था। अपील को स्वीकार करते हुए और उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सबसे पहले, वसीयत में ऐसा कोई खंड नहीं था; दूसरा, यह मानते हुए भी कि इसमें ऐसा कोई खंड था, तो यह केवल वसीयतकर्ता की इच्छा की अभिव्यक्ति थी कि वसीयत की गई संपत्ति से संबंधित विवादों का निपटारा मध्यस्थ द्वारा किया जाना चाहिए और इससे अधिक कुछ नहीं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी भी मामले में वसीयत को मध्यस्थता समझौते का गठन करने के रूप में नहीं माना जा सकता है; तीसरा, भले ही वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत के निष्पादन के बाद इस आशय की कुछ घोषणा की गई हो, क्योंकि यह पिता द्वारा की गई एकतरफा घोषणा थी और इसलिए कल्पना के किसी भी विस्तार से ऐसी घोषणा को उसके बच्चों के बीच मध्यस्थता समझौते के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह की घोषणा को एक पिता की गहरी आशा की अभिव्यक्ति के रूप में लिया जा सकता है कि यदि उनके बीच विवाद उत्पन्न होते हैं तो उनके बच्चों को मध्यस्थता के माध्यम से उनका निपटारा कराना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से यह अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (बी) के अर्थ के भीतर एक मध्यस्थता समझौते की प्रकृति में भाग नहीं लेता है।

पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति रवींद्रन ने पैरा 18 से 22 में इस मुद्दे पर संक्षिप्त रूप से विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"18. इस मामले में, निश्चित रूप से, विवाद के पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित कोई दस्तावेज नहीं है, न ही पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते को संदर्भित करने या रिकॉर्ड करने वाले पत्रों, टेलेक्स, तारों (या दूरसंचार के अन्य साधनों) का कोई आदान-प्रदान है। यह भी विवाद में नहीं है कि दावों या बचाव के बयान का कोई आदान-प्रदान नहीं होता है जहां एक पक्ष द्वारा मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के आरोप को दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में, पक्षों के बीच धारा 7 में परिभाषित कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है।

19. जगदीश चंदर बनाम रमेश चंदर, (2007) 5 एस. सी. सी. 719 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी. पृष्ठ 726, पैरा 11)

"11. अधिनियम की धारा 7 के तहत परिभाषित मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित द्वारा अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। मध्यस्थता समझौते या

आपसी सहमति के अभाव में पक्षों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की अनुमति नहीं है।

20. जबकि उत्तरदाता वसीयत पर भरोसा करते हैं, अपीलार्थी ऐसी किसी भी वसीयत के अस्तित्व से इनकार करता है। ऊपर निर्दिष्ट अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर दो दीवानी मुकदमों में वसीयत की वैधता पर विचार किया जाना बाकी है। कथित वसीयत में, निश्चित रूप से, मध्यस्थता के लिए कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि विद्वत नामित व्यक्ति ने एक गलत धारणा पर आगे बढ़े हैं कि वसीयत में मध्यस्थता का प्रावधान है। भले ही वसीयत में मध्यस्थता के लिए विवादों के संदर्भ का प्रावधान किया गया हो, यह केवल वसीयतकर्ता की इच्छा की अभिव्यक्ति होगी कि विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा किया जाना चाहिए और इसे वसीयतकर्ताओं के बीच मध्यस्थता समझौते के रूप में नहीं माना जा सकता है।

21. इस मामले में, प्रत्यर्थियों के अनुसार, मध्यस्थता का प्रावधान वसीयत में नहीं है, बल्कि दुर्गनारायण शर्मा द्वारा कथित रूप से की गई एक बाद की घोषणा में है, जिसमें कहा गया है कि यदि उनकी वसीयत दिनांक 28.12.2003 के संबंध में कोई विवाद है, तो इसे उनके मित्र, यू. एन. भंडारी, अधिवक्ता को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में भेजा जाएगा,

जिसका निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। एक पिता द्‌वारा एकतरफा घोषणा कि बेटों के बीच भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा उसके द्‌वारा नामित मध्यस्थ द्‌वारा किया जाना चाहिए, किसी भी तरह से उसके बच्चों या उसके ऐसे बच्चों के बीच मध्यस्थता समझौते के रूप में नहीं माना जा सकता है जो किसी विवाद में पक्षकार बन जाते हैं। सबसे अच्छा, इस तरह की घोषणा एक पिता द्‌वारा एक प्यारी आशा की अभिव्यक्ति हो सकती है कि उसके बच्चों को, किसी विवाद की स्थिति में, मध्यस्थता द्‌वारा इसका निपटारा करना चाहिए। यह बच्चों को तय करना है कि वे अपने पिता की सलाह को मानेंगे या नहीं। एक पिता द्‌वारा घोषणा में व्यक्त की गई ऐसी इच्छा, भले ही साबित हो जाए, को विवाद के पक्षों के बीच लिखित समझौते के रूप में नहीं माना जा सकता है जो अपने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए सहमत हैं।

22. इसलिए हमारा विचार है कि पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है और विद्‌वत नामित व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 11 और 15 (2) के तहत आवेदन की अनुमति देने और यह मानने में एक गंभीर त्रुटि की है कि पक्षकारों के बीच एक मध्यस्थता समझौता है और एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया है।

31. जब हम विजय कुमार शर्मा (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित तथ्यों और कानून को ध्यान में रखते हुए मामले के तथ्यों की जांच करते हैं, तो हम तथ्यों और कानून में समानता पाते हैं।

32. यद्यपि विजय कुमार शर्मा का मामला "वसीयत" के निष्पादन से संबंधित एक मामले से संबंधित है, जबकि वर्तमान मामला "न्यास विलेख" के निष्पादन से संबंधित है, फिर भी, हमारे सुविचारित विचार में, जहां तक विजय कुमार शर्मा में निर्धारित कानून के सिद्धांत के मामले के तथ्यों पर लागू होने का संबंध है, इससे कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता है।

33. कारण खोजने के लिए बहुत दूर नहीं हैं। वसीयत के मामले में, वसीयतकर्ता वसीयतकर्ता के पक्ष में वसीयत निष्पादित करता है, जबकि न्यास के मामले में, निपटानकर्ता लाभार्थियों के पक्ष में विलेख निष्पादित करता है। दोनों ही मामलों में, वसीयतकर्ता/अधिवासी ही दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करता है। इसके अलावा, दोनों विलेख वसीयतकर्ताओं या/और लाभार्थियों के पक्ष में संपत्ति में रुचि को व्यक्त करते हैं। हालाँकि, चूंकि वसीयतकर्ता/लाभार्थी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या हम कह सकते हैं कि ऐसे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वसीयतकर्ता/लाभार्थियों/न्यासियों द्वारा विलेख स्वीकार करने के बावजूद उन्हें ऐसे विलेख का पक्षकार नहीं माना जाता है। इसलिए, हमारी राय में,

इस तरह के विलेख में ऐसे पक्षों के बीच समझौते की प्रकृति शामिल नहीं है।

34. इसलिए, हमारा विचार है कि यदि वसीयत में एक मध्यस्थता खंड होने के बावजूद एक मध्यस्थता समझौते का गठन नहीं किया जाता है, तो न्यास विलेख को एक मध्यस्थता खंड होने के बावजूद एक मध्यस्थता समझौते से बहुत कम समझौते का गठन करने के लिए भी नहीं माना जा सकता है।

35. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हमारा मानना है कि मध्यस्थता खंड (खंड 20) सहित न्यास विलेख अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (बी) और 2 (एच) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और इसलिए न्यास विलेख को अधिनियम की धारा 7 के अर्थ के भीतर "मध्यस्थता समझौते" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

36. उपरोक्त मुद्दे की जांच एक अन्य कोण से की जा सकती है जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बिजॉय बल्लव कुंडू और अन्न बनाम तापेती रंजन कुंडू, ए. आई. आर. 1965 कलकत्ता 628 में जांच की थी।

37. बिजॉय बल्लव कुंडू के मामले (उपरोक्त) के तथ्य यह थे कि कलकत्ता के निवासी धनंजय कुंडू एक घर के मालिक थे। उन्होंने एक न्यास/निपटान विलेख निष्पादित किया जिसमें उन्होंने न्यास के मामलों के

प्रबंधन के लिए दो न्यासियों को नामित किया। उन्होंने लाभार्थियों के लाभ के लिए अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए न्यास के कोष के रूप में न्यासियों को 500/- रुपये के साथ अपना घर दिया। न्यास विलेख में कई खंड थे जिनमें यह प्रावधान किया गया था कि न्यासी और लाभार्थियों को न्यास की गतिविधियों को कैसे पूरा करना चाहिए, उन्हें न्यास के मामलों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए और इसके खातों को कैसे बनाए रखना चाहिए आदि खंड 12 में प्रावधान किया गया है कि न्यासियों के बीच प्रबंधन और न्यास के मामलों से संबंधित किसी भी विवाद/मतभेद की स्थिति में, उसे नामित मध्यस्थ को भेजा जाएगा जो भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अनुसार विवादों का फैसला करेगा।

38. कुछ समय बाद न्यासियों के बीच न्यास के मामलों और प्रबंधन को लेकर विवाद पैदा हो गए। तदनुसार उन्हें उनके निर्णय के लिए खंड 12 के संदर्भ में मध्यस्थ के पास भेजा गया था। हालाँकि, एक न्यासी ने मध्यस्थ को निर्देश देने पर आपत्ति जताई। हालाँकि, मध्यस्थ ने पुरस्कार दिया। एक न्यासी, जिसने मध्यस्थ को निर्देश देने पर आपत्ति जताई थी, ने अन्य बातों के साथ-साथ दीवानी न्यायालय में निर्णय की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि चूंकि मध्यस्थ को निर्देश देने के लिए पक्षों (न्यासियों) के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था और इसलिए मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को बिना किसी अधिकार क्षेत्र के

प्रस्तुत किया जाता है और इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है। अदालत ने आपत्ति को बरकरार रखा और पुरस्कार को रद्द कर दिया। पीड़ित न्यासी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की।

39. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने सुविचारित निर्णय द्वारा न्यास अधिनियम और मध्यस्थता अधिनियम 1940 के प्रावधानों के संदर्भ में मुद्दे की जांच की और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया। उनके प्रभुत्व के तर्क का उल्लेख नीचे करना उचित हैः

"5 .... हालाँकि इस मामले में सवाल यह है कि क्या न्यासियों को उनके विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए किसी भी समझौते का पक्षकार कहा जा सकता है। श्री बसाक जिस तरह से तर्क देते हैं वह यह हैः उनका कहना है कि समझौता विलेख यह निर्देश देता है कि मध्यस्थता का ऐसा संदर्भ होगा और न्यासियों को न्यासी स्वीकार करने और न्यासियों के रूप में कार्य करने के लिए सहमत होने में उनके आचरण द्वारा उस समझौते का पक्षकार कहा जाना चाहिए या उनके आचरण से समझौते का पक्षकार बनना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक बार जब वे न्यास को स्वीकार कर लेते हैं, तो उन्हें मध्यस्थता के संदर्भ में समझौते का पक्षकार माना जाना चाहिए, जो विद्वान वकील के अनुसार मध्यस्थता खंड में निहित है। मेरी राय में, यह तर्क सही नहीं है। समझौता बनने के लिए

एक प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए। यदि हमें यह मानना है कि मध्यस्थता खंड लिखित समझौते का गठन करता है, तो हमें यह मानना होगा कि प्रत्येक न्यासी ने, किसी समय, अन्य न्यासी या न्यासियों को एक प्रस्ताव दिया है कि क्या विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए और उनमें से प्रत्येक ने इसे स्वीकार कर लिया है। इस मामले की परिस्थितियों में यह कभी नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कोई घटना कभी हुई हो। न्यास को स्वीकार करके, एक न्यासी केवल न्यास की शर्तों का पालन करने का वचन देता है, जहाँ तक वह कानून के अनुसार हो। मध्यस्थता का संदर्भ निपटान विलेख की कई शर्तों में से केवल एक है। अन्य निर्देश हैं, उदाहरण के लिए, विभिन्न मामलों या किए गए विविध कार्यों पर खर्च की जाने वाली राशि के बारे में निर्देश। यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि न्यास को स्वीकार करने में न्यासियों के आपस में सहमत होने का कोई सवाल है कि ऐसी राशि खर्च की जानी चाहिए या ऐसे कार्य किए जाने चाहिए। न्यासी होने के नाते, वे निपटान विलेख के प्रावधानों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। आपस में किसी भी समझौते का कोई सवाल नहीं हो सकता है; अन्यथा हम इस बेतुकी स्थिति का सामना कर रहे हैं कि विश्वास पत्र के प्रत्येक प्रावधान के संबंध में हमें न्यासियों को एक प्रस्ताव और स्वीकृति देकर इसे पूरा करने के लिए आपस में सहमत होने की कल्पना करनी होगी। विद्वान न्यायाधीश ने इंगित किया है कि किसी न्यास को स्वीकार करने के लिए अन्य न्यासियों को ऐसा करने की इच्छा

या कुछ भी करने के लिए कोई समझौता करने या कुछ भी करने से दूर रहने का संकेत देना आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक न्यासी द्वारा किसी भी प्रस्ताव या दूसरे द्वारा उसे स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह कहना एक आकर्षक तर्क हो सकता है कि न्यासियों ने न्यास के विलेख के तहत न्यासी को स्वीकार करने के लिए सहमति दी है और इसमें निहित प्रत्येक कार्यकाल को पूरा करने के लिए सहमत होना चाहिए। हालाँकि यह कहने से काफी अलग है कि उन्होंने ऐसा करने के लिए आपस में एक लिखित समझौता किया है। विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का प्रावधान एक ऐसा मामला है जो अदालतों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। आम तौर पर, न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्साही होते हैं और केवल कानून के कुछ प्रावधानों द्वारा इसे कम करने की अनुमति दे सकते हैं। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान इस तरह के कानून का गठन करते हैं, लेकिन प्रावधान का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। ताकि मध्यस्थता का कोई संदर्भ हो जो न्यायालयों की अधिकारिता को समाप्त कर दे, पक्षों को एक मध्यस्थता समझौता करना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जिसे कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और किसी दिए गए मामले में यह दिखाया जाना चाहिए कि पक्षों ने कानूनी रूप से ऐसा समझौता किया है और अस्तित्व में एक वैध समझौता है। इससे कम कुछ भी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं कर सकता है और कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में मध्यस्थता या उसके

परिणामस्वरूप किसी निर्णय के किसी भी संदर्भ का समर्थन नहीं किया जा सकता है और इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। हमारी राय में, विद्वान न्यायाधीश द्वारा किए गए निष्कर्ष उस बिंदु पर सही हैं और उन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। इस मामले के तथ्यों में यह माना जाना चाहिए कि कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था और मध्यस्थता का कोई वैध संदर्भ नहीं था।

40. हम पाते हैं कि मामले के तथ्य और बिजय बल्लव कुंडू (उपरोक्त) के मामले में शामिल तथ्य समान हैं। हम उनके प्रभुत्व के उपरोक्त तर्क से सहमत हैं, जो हमारी राय में, इस विषय पर कानून के सही सिद्धांत को निर्धारित करता है। वास्तव में, उनके नेतृत्व ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 2 (ए) में परिभाषित "मध्यस्थता समझौते" की परिभाषा के संदर्भ में मुद्दे की जांच की, जबकि अधिनियम 1996 की धारा 2 (बी) और 2 (एच) के साथ पठित धारा 2 (बी) और 2 (एच) में परिभाषित "मध्यस्थता समझौते" की परिभाषा के संदर्भ में मामले की जांच करने की आवश्यकता है, जो पहले की परिभाषा से काफी अलग है।

41. जैसा कि विजय बल्लव कुंडू (उपरोक्त) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, प्रत्येक समझौते के मामले में हमेशा एक प्रस्ताव और फिर इसकी स्वीकृति होती

है, जिसकी न्यास के निर्माण के मामले में आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यास के मामले में न्यासी और लाभार्थी हालांकि इसके निर्माण को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस तरह की स्वीकृति से, वे केवल न्यास विलेख की शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं जहां तक वह कानून के अनुसार हो। न्यास विलेख में मध्यस्थता से संबंधित खंड कई खंडों में से एक है। अन्य खंड जो न्यासियों और लाभार्थियों को कई प्रकार के निर्देशों से संबंधित हैं जैसे कि न्यास का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, न्यास की राशि कैसे खर्च की जानी चाहिए आदि न्यासियों या/और लाभार्थियों के बीच समझौते की प्रकृति में नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, न्यास विलेख को स्वीकार करके, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यासी या लाभार्थी आपस में इस बात पर सहमत हुए हैं कि उन्हें धन कैसे खर्च करना चाहिए या उन्हें न्यास के मामलों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए या कोई लाभ कैसे प्राप्त करना चाहिए।

42. वास्तव में, ऐसे मामले में, न्यासियों या/और लाभार्थियों को केवल न्यास विलेख के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए, इस तरह की किसी भी गतिविधि को करने के लिए न्यासियों या लाभार्थियों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होना है तो न्यासियों/लाभार्थियों को न्यास विलेख के प्रत्येक खंड के संबंध में प्रस्ताव

और स्वीकृति देनी होगी। तब यह सरासर बेतुकी बात होगी और इसलिए हमारे विचार में ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

43. जैसा कि बिजय बल्लव कुंडू (उपर्युक्त) में उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, जिसके लिए हम सहमत हैं कि एक समझौते का खंड, जो निजी मध्यस्थता के माध्यम से ऐसे समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने का प्रावधान करता है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करता है और न्यायालयों की अधिकारिता को हटाने का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मध्यस्थता अधिनियम एक ऐसा कानून है, जो सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हटाने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, मध्यस्थता के माध्यम से किसी समझौते के पक्षों के बीच विवादों को तय करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हमारी राय में, इस तरह के खंड के लिए यह पता लगाने के लिए व्याख्या के सख्त नियम की आवश्यकता है कि क्या यह अधिकार क्षेत्र को हटाने का प्रावधान करता है और यदि ऐसा है, तो किस न्यायालय/न्यायाधिकरण/प्राधिकरण के लिए मामला हो सकता है। हाथ में मामले में, जब हम व्याख्या के इस सिद्धांत को लागू करते हैं, तो हम यह नहीं पाते हैं कि खंड 20 मध्यस्थ को लाभार्थियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण

करने में सक्षम बनाता है। दूसरे शब्दों में, खंड 20 अधिनियम की धारा 2 (बी), 2 (एच) और 7 की कठोरता को संतुष्ट नहीं करता है।

44. ऊपर हमने जो चर्चा की है, उसके आलोक में, हमारी यह सुविचारित राय है कि न्यास विलेख में खंड 20, जो न्यास के लाभार्थियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों/मतभेदों के निपटारे का प्रावधान करता है, अधिनियम की धारा 7 के अर्थ के भीतर स्वयं लाभार्थियों के बीच एक मध्यस्थता समझौते का गठन नहीं करता है।

45. यह हमें अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर नाफडे के तीसरे तर्क पर विचार करने के लिए ले जाता है। यद्यपि हम ऊपर जो मान चुके हैं, उसे ध्यान में रखते हुए इस तर्क पर विचार करना आवश्यक नहीं हो सकता है, फिर भी हम महसूस करते हैं कि चूंकि यह इस मामले से उत्पन्न होता है और एक विशुद्ध कानूनी प्रश्न होने के कारण, इस अपील में इसका निर्णय लिया जा सकता है।

46. विद्वान वकील का तर्क था कि न्यास के प्रबंधन और मामलों से संबंधित कोई भी विवाद, जिसमें न्यासियों और न्यास, उसके मामलों, प्रबंधन और संपत्तियों के संबंध में लाभार्थियों के बीच विवाद शामिल हैं, अधिनियम के तहत मध्यस्थ द्वारा तय नहीं किया जा सकता है, भले ही विलेख में इस आशय का एक खंड हो। यह उनका निवेदन था कि मध्यस्थता के माध्यम से ऐसे विवादों का निर्णय लेने का उपाय, यदि नहीं,

तो योजना और न्यास अधिनियम के विस्तृत प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट रूप से वर्जित है। विद्वान वकील ने बताया कि न्यास अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और न्यास, न्यासियों और लाभार्थियों से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करता है, जिसमें उनके और न्यास के बीच उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी विवादों के निर्णय के लिए पर्याप्त मंच (सिविल कोर्ट) प्रदान करना शामिल है, और इसलिए, सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कानून में मान्यता प्राप्त अधिकार क्षेत्र के निहित बार को लागू करके अधिनियम के तहत निजी मध्यस्थता की अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार के लिए प्रबल प्रभाव दिया जाना चाहिए।

47. यद्यपि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के उपरोक्त प्रस्तुतिकरण का विरोध किया, लेकिन हम उल्लिखित कारणों के लिए अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील को प्रस्तुत करने में योग्यता पाते हैं।

48. न्यास अधिनियम की योजना की जांच करने से पहले, हम मामले के कानून पर ध्यान देना उचित समझते हैं, जिसका इस मुद्दे पर प्रभाव पड़ता है। बोज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक बनाम एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य के मामले में यह सवाल इस अदालत के समक्ष विचार के लिए आया। (2011) 5 एस. सी. सी. 532 इस बारे में कि

"मध्यस्थता" शब्द का क्या अर्थ है और दूसरा, किस प्रकार के विवाद अधिनियम के तहत मध्यस्थता द्‌वारा निपटाने में सक्षम हैं। उनके अध्यक्षों ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तीन प्रश्न तैयार किए-(1) क्या उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विवादों को पक्षों द्‌वारा चुने गए एक निजी मंच (मध्यस्थता न्यायाधिकरण) द्‌वारा हल किया जा सकता है या क्या ऐसे विवाद विशेष रूप से सार्वजनिक मंच (न्यायालयों) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं; (2) क्या विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे में आते हैं; और (3) क्या पक्षों ने विवादों को मध्यस्थ को भेजा है?

49. इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति रवींद्रन के माध्यम से बोलते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देते समय, जिसके साथ हम यहाँ संबंधित हैं, उनके प्रभुत्त्व ने मामलों की छह श्रेणियों को तराशा। इन छह श्रेणियों के मामलों को मध्यस्थता अधिनियम के तहत निजी मध्यस्थता द्‌वारा निर्णय लेने में सक्षम नहीं माना गया था, भले ही पक्ष निजी मध्यस्थता के माध्यम से उनके निपटारे के लिए सहमत हुए हों। पेरा 35 और 36 में उनके प्रभुत्त्व इस प्रकार थेः

"35. मध्यस्थ न्यायाधिकरण निजी मंच हैं जो देश के कानूनों के तहत गठित अदालतों और न्यायाधिकरणों के स्थान पर अपने विवादों पर निर्णय लेने के लिए विवाद के पक्षों द्‌वारा स्वेच्छा से चुने जाते हैं। प्रत्येक दीवानी या वाणिज्यिक विवाद, या तो संविदात्मक या गैर संविदात्मक,

जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, सैद्धांतिक रूप से मध्यस्थता द्वारा निर्णय लेने और हल करने में सक्षम है जब तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरणों की अधिकारिता को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा बाहर नहीं रखा जाता है। कार्यवाहियों की कुछ श्रेणियों का निर्णय विधायिका द्वारा सार्वजनिक नीति के मामले में विशेष रूप से सार्वजनिक मंचों के लिए आरक्षित है। कुछ अन्य श्रेणियों के मामले, हालांकि सार्वजनिक मंचों (न्यायालयों और न्यायाधिकरणों) द्वारा निर्णय के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षित नहीं हैं, आवश्यक निहितार्थ से निजी मंचों के दायरे से बाहर हो सकते हैं। नतीजतन, जहां कारण/विवाद अविवेकी है, वह न्यायालय जहां एक मुकदमा लंबित है, अधिनियम की धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर देगा, भले ही पक्षकार ऐसे विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता पर सहमत हुए हों।

36. गैर-मध्यस्थता विवादों के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त उदाहरण हैंः (i) उन अधिकारों और देनदारियों से संबंधित विवाद जो आपराधिक अपराधों को जन्म देते हैं या उत्पन्न होते हैं; (ii) तलाक, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बाल अभिरक्षा से संबंधित वैवाहिक विवाद; (iii) संरक्षकता के मामले; (iv) दिवालियापन और समापन के मामले; (v) वसीयती मामले (प्रोबेट, प्रशासन के पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का अनुदान); और (vi) विशेष कानूनों द्वारा शासित बेदखली या

किरायेदारी के मामले जहां किरायेदार को बेदखली के खिलाफ वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है और केवल निर्दिष्ट अदालतों को बेदखली देने या विवादों का फैसला करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है।

50. इस अपील में विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या न्यास के मामलों और प्रबंधन से संबंधित विवाद, जिसमें न्यासियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद, उनकी नियुक्ति के संबंध में लाभार्थी, शक्तियां, कर्तव्य, दायित्व, निष्कासन आदि शामिल हैं, अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेकर मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए जाने में सक्षम हैं, यदि न्यास विलेख में इस आशय का कोई खंड है या ऐसे विवादों का निर्णय न्यास अधिनियम के तहत उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित मंच की सहायता से किया जाना है।

51. कानून के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, आइए अब हम न्यास अधिनियम की योजना की जांच करें। न्यास अधिनियम को स्वतंत्रता से बहुत पहले निजी न्यासों और न्यासियों से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में 93 धाराएँ हैं, जिन्हें नौवें अध्याय में विभाजित किया गया है।

52. अध्याय I संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, अधिनियमों के निरसन और शब्दों की व्याख्या (धारा 1 से 3) से संबंधित है। अध्याय II एक न्यास

(धारा 4 से 10) के निर्माण से संबंधित है। अध्याय III न्यासियों के कर्तव्यों और देनदारियों से संबंधित है (धारा 11 से 30)। अध्याय IV न्यासियों के अधिकारों और शक्तियों (धारा 31 से 45) से संबंधित है। अध्याय 5 न्यासियों की अक्षमताओं से संबंधित है (धारा 46 से 54)। अध्याय VI लाभार्थियों के अधिकारों और देनदारियों (धारा 55 से 69) से संबंधित है। अध्याय VII न्यासी के कार्यालय को खाली करने से संबंधित है (धारा 70 से 76)। अध्याय VIII न्यासों के विलुप्त होने (धारा 77 से 79) से संबंधित है और अध्याय IX न्यास की प्रकृति (धारा 80 से 93) में कुछ दायित्वों से संबंधित है।

53. प्रत्येक अध्याय के शीर्षकों के सरसरी अवलोकन से भी पता चलता है कि विधायिका ने प्रत्येक विषय पर व्यापक और पर्याप्त रूप से ध्यान दिया है। यह न्यास के निर्माण से शुरू होता है कि इसे कैसे बनाया जाना चाहिए (विलेख), कौन बना सकता है (न्यास/अधिवासी का लेखक), कौन प्रबंधन कर सकता है (न्यासी), जिसके लाभ के लिए इसे बनाया जा सकता है (लाभार्थी), नियुक्ति के लिए उनकी योग्यताएँः हटाने के लिए आधार, अधिकार और कर्तव्य, उनकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध, शिकायतों को निपटाने के लिए उपलब्ध दायित्व और कानूनी उपाय आदि सभी ट्रस्ट अधिनियम में निर्दिष्ट हैं।

54. जहाँ तक न्यास/अधिवासी के लेखक, न्यासी और लाभार्थियों को न्यास विलेख और न्यास अधिनियम के तहत अपने अधिकार कर्तव्यों, हटाने और दायित्वों के संबंध में अपनी कई शिकायतों को उजागर करने के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय हैं, वे विशेष रूप से न्यास अधिनियम की धारा 7,11,34,36,41,45,46,49,53,71,72,73 और 74 में प्रदान किए गए हैं। ये धाराएँ, विशिष्ट शब्दों में, सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करती हैं और यह प्रावधान करती हैं कि एक पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों के न्यायनिर्णयन के लिए मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख सिविल न्यायालय से संपर्क कर सकता है। यह स्पष्ट रूप से विधायिका के इरादे को दर्शाता है कि विधायिका ट्रस्ट अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने के लिए केवल दीवानी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का इरादा रखती है।

55. धुलाभाई आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 78 के एक प्रमुख मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस सवाल की जांच की कि किसी विशेष कानून में बनाए गए स्पष्ट या निहित बार के संदर्भ में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए। उनके लॉर्डशिप्स ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 और विशेष कानून में बनाए गए बार के संदर्भ में प्रश्न की जांच की।

56. न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, पीठ की ओर से बोलते हुए सिविल न्यायालय या किसी विशेष कानून के तहत गठित न्यायिक न्यायाधिकरणों/प्राधिकरणों में उपचारों पर मुकदमा चलाने के लिए बार के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए 7 शर्तें निर्धारित कीं। यद्यपि धुलाभाई के मामले (उपरोक्त) में जिस मुद्दे की जांच की गई है, वह एक पीड़ित पक्ष द्वारा दीवानी मुकदमा दायर करने के संबंध में विशेष कानून में बनाए गए प्रतिबंध से संबंधित है, फिर भी निर्णय, हमारे विचार में, सामान्य सिद्धांत को निर्धारित करता है कि अदालतों को कानून में उपलब्ध उपचारों के संदर्भ में स्पष्ट या/और निहित प्रतिबंध के मुद्दे का निर्णय कैसे करना चाहिए।

57. जहाँ तक मामले में शामिल प्रश्न का संबंध है, यह धुलाभाई के मामले (उपरोक्त) की शर्त संख्या 2 द्वारा शासित है जो निम्नानुसार हैः

"(2) जहां न्यायालय की अधिकारिता की एक स्पष्ट बाधा है, वहां प्रदान किए गए उपचारों की पर्याप्तता या पर्याप्तता का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की योजना की जांच प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को बनाए रखने के लिए निर्णायक नहीं है। जहां कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है, वहां उपचारों की जांच और इरादे का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की योजना आवश्यक हो जाती है और जांच का परिणाम निर्णायक हो सकता है। बाद के मामले में यह आवश्यक है कि क्या क़ानून एक विशेष अधिकार या दायित्व पैदा करता है

और अधिकार या दायित्व के निर्धारण के लिए प्रावधान करता है और आगे यह निर्धारित करता है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न इस प्रकार गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और क्या सिविल अदालतों में कार्यों से जुड़े उपचार उक्त क़ानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं या नहीं।

58. जब हम शर्त संख्या 2 में निर्धारित सिद्धांत के आलोक में न्यास अधिनियम की योजना की जांच करते हैं, तो हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई नहीं होती है कि यद्यपि न्यास अधिनियम न्यास अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने के लिए अन्य अधिनियमों की प्रयोज्यता के संबंध में कोई स्पष्ट बाधा प्रदान नहीं करता है, हमारे विचार में, निजी मध्यस्थता के माध्यम से न्यास, न्यासियों और लाभार्थियों से संबंधित विवादों को तय करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की प्रयोज्यता का एक निहित बहिष्कार मौजूद है। दूसरे शब्दों में, जब न्यास अधिनियम न्यास, न्यासियों और लाभार्थियों के साथ व्यापक रूप से व्यवहार करता है और सभी पीड़ित व्यक्तियों को न्यास विलेख और न्यास अधिनियम से उत्पन्न होने वाले अपने विवादों के निवारण के लिए मूल मूल अधिकार क्षेत्र के सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देकर पर्याप्त और पर्याप्त उपचार प्रदान करता है, तो हमारी राय में न्यास के मामलों से संबंधित किसी भी विवाद, जिसमें न्यासी और

लाभार्थी के बीच उनके अधिकार, कर्तव्यों, दायित्वों, हटाने आदि के संबंध में विवाद शामिल है, का निर्णय मध्यस्थ द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेकर नहीं किया जा सकता है। इस तरह के विवादों का निर्णय न्यास अधिनियम के तहत निर्दिष्ट दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाना है।

59. व्याख्या का सिद्धांत कि जहां एक विशिष्ट उपाय दिया जाता है, यह उस व्यक्ति को वंचित करता है जो कानून द्वारा दिए गए उपचार के अलावा किसी अन्य प्रकार के उपचार पर जोर देता है, वह बहुत परिचित है, और जो कानून के माध्यम से चलता है, इस न्यायालय द्वारा द प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाम कमलाकर शांताराम वाडके और अन्य, ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 2238 के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपचार के संदर्भ में दीवानी मुकदमा दायर करने में बार के प्रश्न की जांच करते हुए अपनाया गया था (जी. पी. सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत, 12 संस्करण, पृष्ठ 763-764)। हम इस सिद्धांत को यहां लागू करते हैं क्योंकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न्यास अधिनियम एक दायित्व पैदा करता है और न्यास विलेख में निर्दिष्ट कई शर्तों के अलावा बसने वाले, न्यासियों और लाभार्थियों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है और आगे सिविल कोर्ट में आवेदन दायर करके इसके प्रवर्तन के लिए एक विशिष्ट

उपाय प्रदान करता है। यही कारण है कि हमारा विचार है कि चूंकि न्यास विलेख, न्यासियों और लाभार्थियों के संबंध में विवादों को तय करने के लिए न्यास अधिनियम के तहत पर्याप्त और पर्याप्त उपाय प्रदान किया गया है, इसलिए ऐसे विवादों को तय करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम के तहत प्रदान किया गया उपाय निहितार्थ से वर्जित है।

60. हालाँकि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने कुछ प्रस्तुतियाँ करके उच्च न्यायालय द्वारा किए गए तर्क और निष्कर्ष का समर्थन करने का प्रयास किया, लेकिन हम उनमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं, विशेष रूप से ऊपर जो हमने माना है, उसके आलोक में। इसलिए, हम उनके निवेदन को अस्वीकार करने के लिए अपना विस्तृत तर्क देना आवश्यक नहीं समझते हैं और न ही उनके द्वारा उद्धृत निर्णय (एम. सी. चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर त्रिवेंद्रम, (1970) 1 एस. सी. सी. 658) से निपटना आवश्यक समझते हैं, जो तथ्यों पर अलग है।

61. हम, तदनुसार, मानते हैं कि न्यास विलेख और न्यास अधिनियम से उत्पन्न न्यास, न्यासियों और लाभार्थियों से संबंधित विवाद पक्षों के बीच उस प्रभाव के लिए मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बावजूद मध्यस्थ द्वारा तय किए जाने में सक्षम नहीं हैं। ए फोर्टियोरी-हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा दायर आवेदन इस आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं है कि पहला, यह

अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (बी) और 2 (एच) के अर्थ के भीतर एक "मध्यस्थता समझौते" पर आधारित नहीं है और दूसरा, यह मानते हुए कि एक मध्यस्थता समझौता (न्यास विलेख का खंड 20) मौजूद है, फिर भी उसमें निर्दिष्ट विवाद गुण-दोष पर अपने निर्णय के लिए निजी मध्यस्थता को भेजे जाने में सक्षम नहीं हैं।

62. इस प्रकार हम बूज़ ऐलन एंड हैमिल्टन इंक. (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के पृष्ठ 547 पर पैरा 36 में इस न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मामलों की (vi) श्रेणियों की सूची में मामलों की एक और श्रेणी, अर्थात् न्यास विलेख और न्यास अधिनियम से उत्पन्न होने वाले मामलों, श्रेणी (vii) को जोड़ते हैं, जो उपरोक्त रूप से मध्यस्थताओं द्वारा तय नहीं किए जा सकते हैं।

63. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम विद्वान नामित मध्यस्थ द्वारा किए गए तर्क और निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं।

64. मामला छोड़ने से पहले, हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि हमने इन कार्यवाहियों में पक्षों द्वारा स्थापित मामले के गुण-दोष की जांच नहीं की है और इसलिए पक्ष अपने अधिकारों के निर्णय के लिए किसी भी कानूनी उपाय का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो उनके लिए उपलब्ध हो।

65. इस प्रकार अपील सफल हो जाती है और इसके लिए अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। नतीजतन, अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन को विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

अपील को मंजूरी दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सपना राजपुरोहित द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।